1956 की धारा 51 (2) के अनुसार भोपाल में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने के लिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः, मामला केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Lawyer's strike

4003. SHRI IQBAL SINGH : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the strike by lawyers of Tis Hazari Court in Delhi;

(b) if so, what measures Government have thought of persuading lawyers not to go on strike of and on ;

(c) whether Government are aware of the plight of litigants who are to suffer for no fault of them ; and

(d) whether any code of conduct for the lawyers will be formulated in consultation with Bar Councils and Judiciary to avoid strikes by the lawyers in the country ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d) A resolution adopted by the Chief Ministers and Chief Justices in their meeting held in December, 1993 recommended the constitution of committees of lawyers and judges at the appropriate levels to go into problems concerning lawyers' strikes and evolve appropriate guidelines for preventing indiscriminate closure of Courts. Copies of this Resolution have been forwarded to the Supreme Court, all High Courts and to the Bar Council of India for taking necessary follow-up action.

Locations for wind farms in Karnataka

4004. SHRI B. K. HARIPRASAD : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government have taken note of the success achieved so far by the private sector in promoting wind energy as a viable and cheaper alternative to conventional energy ; and

(b) whether Government have undertaken any wind mapping programme to help identify location for wind farms and if so, how many of such locations have been identified for Karnataka ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI S. KRISHNA KUMAR) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir. A comprehensive wind survey programme comprising wind mapping, wind monitoring and complex terrain projects is being undertaken by Ministry of Non-Conventional Energy Sources in 23 States/UTs to assess the potential and identify sites for wind energy projects. Eight potential locations have so far been identified in Karnataka for establishment of wind power projects.

हिन्द महासागर में खनन क्षेत्र

4005. श्री मूलचंद मीणा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण से हिन्द महासागर में अनेक खनन क्षेत्रों का पता लगाने में सहायता मिली है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये खनन क्षेत्र हमारे देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र से बाहर हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इन क्षेत्रों के दोहन का अधिकार प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री एडुआर्डो फेलेरियो) : (क) और (ख) जी हाँ, श्रीमान। वर्ष 1987 में भारत को एक अग्रणी निवेशक के रूप में पंजीकरण प्राप्त हुआ तथा मध्य हिन्द महासागर में इसे 1,50,000 वर्ग किलोमीटर का खान स्थल आवंटित किया गया। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने, छोड़े जाने वाले 50 प्रतिशत क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए सम्पूर्ण क्षेत्र के अनुगंभीर सर्वेक्षण पूरे कर लिए हैं।

(ग) जी हाँ, श्रीमान। ये खनन क्षेत्र हमारे देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाहर हैं।

(घ) समुद्र विधि पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन से संलग्न संकल्प-2 के अन्तर्गत भारत तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता को प्रमाणित करने के बाद खनन क्षेत्र में संसाधनों के दोहन के लिए कदम उठा सकता है।

सरकारी कर्मचारियों के सेवाओं के मामले के संबंध में संसद-सदस्यों द्वारा पत्र

4006. श्री रामदेव भंडारी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी संसद सदस्य द्वारा किसी अधिकारी की पदस्थापना के संबंध में मंत्री/अध्यक्ष को लिखे गए अनुरोध पत्र को राजनीतिक अथवा बाहरी दबाव समझा जाता है ;